



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007 / 16 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 28 अगस्त, 2007

संख्या : वि० स०-विधायन-गवर्न. बिल, 1-38/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 28-8-2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव।

**हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन
विधेयक, 2007**

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन ।

**हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया
वसूली) संशोधन विधेयक, 2007**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली)
अधिनियम, 1971 (1971 का 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2007 है।

2. हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप-खण्ड (i) में, “सुधार न्यास” शब्दों के पश्चात् “या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां” शब्द जोड़े जाएंगे।

धारा 2 का
संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कम्पोजिट पंजाब वक्फ बोर्ड के न्यागमन के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश की वक्फ सम्पत्तियां, अधिसूचना संख्या: रैव-सी (ए) (वक्फ)1-1/2003, तारीख 01 अगस्त, 2003 द्वारा नवसृजित हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीधे नियन्त्रण में आ गई है। इसके अतिरिक्त श्रम एवं कल्याण (13वीं लोक सभा) की स्थायी समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट में भी सिफारिश की है कि वक्फ सम्पत्तियों को सरकारी स्थान अधिनियम के लागू न होने के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अवैध अधिभोगियों से ऐसी सम्पत्तियों के कब्जे प्रत्यावर्तित कराने हेतु सच्चे प्रयास नहीं किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसी कई वक्फ सम्पत्तियां हैं, जिन पर विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कई स्थानों पर अतिक्रमण किया गया है और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को इन मूल्यवान तथा अतिक्रमण की गई सम्पत्तियों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है तथा बोर्ड को अतिक्रमणों को हटाने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड ने पुरजोर सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश की सभी वक्फ सम्पत्तियों को हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के अधीन लाया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण हटाने तथा अपनी आय बढ़ाने हेतु समर्थ बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर विचार करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) को उपयुक्त रूप से संशोधित करके वक्फ सम्पत्तियों को हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 के दायरे में लाने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख : 2007

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

**हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन
विधेयक, 2007**

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मंत्री।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख....., 2007.

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) के उपबन्धों के उद्धरण।

धारा :

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) से (घ) XXX XXX XXX

(ङ) “सरकारी स्थान” से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार का हो या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो या और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

- (i) कोई नगर निगम/समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, पंचायत या “सुधार न्यास”;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी जिसकी समादत शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग राज्य सरकार द्वारा धारित हो;
- (iii) कोई निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकारी नहीं हैं) जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खण्ड (7) में यथापरिभाषित किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अथवा हिमाचल प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन हो;
- (iv) हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी;

(च) से (छ) XXX

XXX

XXX

**THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND
(EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT
BILL, 2007**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CLAUSES:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT BILL, 2007

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (Act No. 22 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2007. Short title.

2. In the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, in section 2, in clause (e), in sub-clause (i), after the words “improvement trust”, the words “or a Wakf property registered with the Himachal Pradesh Wakf Board” shall be added. Amendment of section 2.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After the devolution of composite Punjab Wakf Board, the Wakf Properties of Himachal Pradesh have come under the direct control of newly created Himachal Pradesh Wakf Board *vide* notification No.Rev.-C(A)(Wakf) 1-1/2003, dated 1st August, 2003. Further, the Standing Committee on Labour and Welfare (13th Lok Sabha) in their 12th report has also recommended that on account of non-applicability of the Public Premises Act on Wakf properties no sincere efforts have been made by the State Government/Union Territories to restore the possession of such properties from illegal occupants.

In the State of Himachal Pradesh, the Chairman, Himachal Pradesh Wakf Board has informed that there are number of Wakf properties which have been encroached upon by the various Government/Semi-Government departments and by private persons at various places and Himachal Pradesh Wakf Board is not getting any revenue from these valuable and encroached properties and the Board is facing hindrance in removing the encroachments. The Board has strongly recommended that all the Wakf properties of Himachal Pradesh be brought under the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 enabling the Himachal Pradesh Wakf Board to remove the encroachments and raise its income. After taking into consideration the difficulties which is being faced by the Himachal Pradesh Wakf Board, it has been decided to bring Wakf properties within the ambit of the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 by suitably amending clause (e) of section 2 of the said Act. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

Shimla:

Dated :2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

**THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION
AND RENT RECOVERY) AMENDMENT BILL, 2007**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and
Rent Recovery Act, 1971 (Act No. 22 of 1971).*

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

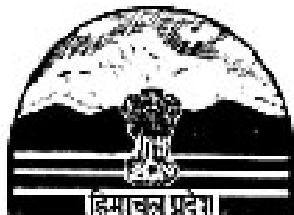
J. N. BAROWALIA,
Pr. Secretary (Law).

Shimla:
The....., 2007.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) ACT, 1971 (ACT NO. 22 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section 2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) to (d) XXX XXX XXX XXX
- (e) “public premises” means any premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of, the State Government and includes any premises belonging to, or taken on lease by, or on behalf of—
- (i) any municipal corporation/committee, notified area committee, panchayat samiti, Panchayat or improvement trust;
 - (ii) any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government;
 - (iii) any corporation (not being a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 or a local authority) established by or under a Central Act as defined in clause (7) of section 3 of the General Clauses Act, 1897, or a Himachal Pradesh Act and owned or controlled by the State Government, and
 - (iv) any cooperative society registered or deemed to have been registered under the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968.
- (f) to (g) XXX XXX XXX XXX



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007/16 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 28 अगस्त, 2007

संख्या : वि० स०-विधायन-गवर्न. बिल, 1-39/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 28-8-2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव।

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 46 का संशोधन।
3. धारा 84 का संशोधन।
4. धारा 161 का संशोधन।
5. धारा 243 का संशोधन।
6. धारा 251 का लोप।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम संक्षिप्त नाम । (संशोधन) अधिनियम, 2007 है ।

1994 का 12 2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें धारा 46 का इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 46 की विद्यमान संशोधन । उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) निगम को सभी विधिक मामलों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी होगा जिसे ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, निगम द्वारा नियुक्त किया जाएगा।"

3. मूल अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1) के विद्यमान खण्ड धारा 84 का (ग) का लोप किया जाएगा । संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (3) में, "निदेशक के धारा 161 का नियन्त्रणाधीन" चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा । संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 243 की उपधारा (2) के विद्यमान धारा 243 का परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- संशोधन ।

“परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश निगम के साथ रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर या वास्तुविद् या योजनाकार या कनिष्ठ अभियन्ता या ड्राफ्ट्समैन द्वारा, ऐसी फीस के संदाय पर जो निगम द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।”।

धारा 251 का
लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 251 का लोप किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन विधिक मामलों में निगम की सहायता और परामर्श देने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर विधि सलाहकार एवं अभियोजक नियुक्त करने का उपबन्ध है। चूंकि निगम में विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया है, इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) में "विधि सलाहकार एवं अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विधि सलाहकार एवं विधि अधिकारी" शब्द रखने तथा शब्द "प्रतिनियुक्ति द्वारा" का लोप करने का विनिश्चय किया गया है।

वर्तमान में, नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे के साथ विक्रय, दान और बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश राज्य में तत्समय यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, नगरपालिका क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर धारा 84 के अधीन नगर निगम द्वारा दो प्रतिशत अधिभार संगृहीत किया जा रहा है। शिमला शहर के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0 एन0 यू0 आर0 एम0) के नाम से एक स्कीम प्रारम्भ की गई है जिसके लिए कतिपय सुधारों के अध्यधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्टाम्प शुल्क को पांच प्रतिशत से अनधिक करके तर्कसंगत बनाना इन सुधारों में से एक है। राज्य सरकार ने इस बाबत भारत सरकार के साथ एम0ओ0ए0 हस्ताक्षरित किया है। राजस्व विभाग ने पहले ही स्टाम्प शुल्क को आठ प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। किन्तु निगम द्वारा दो प्रतिशत अधिभार के संग्रहण से स्टाम्प शुल्क की प्रतिशतता सात प्रतिशत तक बढ़ जाती है जो जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 के अधीन प्रतिबद्ध सुधारों के विरुद्ध है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) का लोप करके उक्त अधिभार को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार नगर निगम निधियों के लेखों की संपरीक्षा निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के नियन्त्रणाधीन स्वतन्त्र संपरीक्षा अभिकरण द्वारा की जाती है। भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय ने ऐसे विकल्पी अभिकरणों, जो राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं हैं, को अनुज्ञात कर, संपरीक्षा अभिकरण की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 161 को उपयुक्त रूप से संशोधित करना अपेक्षित हो गया है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 निगम क्षेत्र में भवन रेखांक (प्लान) और विनिर्देश हस्ताक्षरित करने हेतु केवल अर्हता प्राप्त संरचनात्मक अभियन्ताओं को ही प्राधिकृत करता है। वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविदों ने उपरोक्त उपबन्धों को इस अनुरोध के साथ चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की है कि वास्तुविदों को भी निगम क्षेत्र में रेखांकों को हस्ताक्षरित करने की अनुमति दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने 13-01-2006 के अपने आदेश द्वारा ऐसे वास्तुविदों को, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे रेखांकों और विनिर्देशों को हस्ताक्षरित करने हेतु अनुज्ञात करने का निदेश दिया है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में आवश्यक उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया है।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 251 के अधीन, आयुक्त को भवन निर्माण की मंजूरी देते समय ऐसे संकर्म (निर्माण) के प्रारम्भ होने से भवन के निर्माण के पूर्ण होने तक के लिए, युक्तियुक्त अवधि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति है। यदि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन या संकर्म पूर्ण नहीं होता है तो इस अवधि के विस्तारण हेतु अभिप्राप्त नई मंजूरी के बिना, उसके बाद जारी नहीं रखा जाएगा। इस उपबन्ध को जनसाधारण के हित के विरुद्ध माना गया है, क्योंकि सन्निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) की लागत सदैव ही प्राक्कलित लागत से कहीं अधिक हो जाती है और इस प्रकार, साधारणतया सीमित वित्तीय क्षमता वाले लोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 251 का लोप करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख.....2007

वित्तीय ज्ञापन

— शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

— शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला:

तारीख.....2007.

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) के उपबन्धों के उद्घरण ।

धाराएं :

46. संयुक्त/सहायक आयुक्त और कतिपय अन्य अधिकारियों की नियुक्ति:—(1) राज्य सरकार, यदि उसकी राय में ऐसा करना जनहित में समीचीन है, निगम के कृत्यों के दक्ष पूर्ण निर्वहन के लिए धारा 45 के अधीन नियुक्त आयुक्त की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो संयुक्त/सहायक आयुक्त कहलाएंगे और व सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जा सकेंगी ।

(2) निगम के अनुमोदन और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त संयुक्त/सहायक आयुक्त, आयुक्त के अधीनस्थ होंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि इस अधिनियम के अधीन आयुक्त को प्रदत्त और अधिरोपित किए जा सकेंगे और जो उन्हें आयुक्त द्वारा आगे प्रत्यायोजित किए गए हैं ।

(3) निगम को सभी विधिक मामलों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक विधि सलाहकार एवं अभियोजक होगा जिसे निगम द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा, नियुक्त किया जाएगा, जैसी विहित की जाएं ।

84. इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर इत्यादि और सरकार द्वारा संगृहीत कतिपय करों का प्रबन्ध.—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगा :—

(क) से (ख) XXX XXX XXX

(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण पर, विक्रय, दान और स्थावर सम्पत्ति के कब्जा सहित बन्धक लिखत पर, ऐसी दर पर जैसा कि सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे, जो कि प्रतिफल की राशि, सम्पत्ति के मूल्य या लिखत में यथा उपवर्णित बंधक द्वारा प्रतिभूत राशि के एक प्रतिशत से अन्यून और दो प्रतिशत से अनधिक शुल्क के रूप में;

उक्त शुल्क, दस्तावेज के पंजीकरण के समय न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी सूचना निगम को तुरन्त भेज दी जाएगी । इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि निगम को संदत्त कर दी जाएगी ।

(2) सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करें के अतिरिक्त, निम्नलिखित उद्गृहीत करेगा—

(क) से (छ) XXXX XXXX XXXX

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कर तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को विहित रीति में आक्षेप करने का अवसर नहीं दे दिया जाता और आक्षेपों, यदि कोई प्राप्त हुए हों, पर विचार नहीं कर लिया जाता ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट करें का उदग्रहण ऐसी दर से किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित और संगृहीत किया जाएगा;

(4) सरकार उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन आने वाले ऐसे करें को जो कि निगम द्वारा पहले से ही ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि में अधिरोपित नहीं किए गए हैं, अधिरोपित करने के लिए विशेष या साधारण आदेश दे सकेगी और निगम तदनुसार कार्य करेगा;

(5) यदि निगम उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश के कार्यान्वयन में असफल रहता है तो सरकार राजपत्र में अधिसूचित उपयुक्त आदेश द्वारा कर अधिरोपित कर सकेगी और इस प्रकार पारित आदेश ऐसे लागू होगा जैसे कि कर, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा सम्यक् रूप से अधिरोपित किया गया है ।

161. रखे जाने वाले खाते.—(1) निगम अपनी सभी प्राप्तियों और व्ययों के निम्नलिखित चार पृथक खाते विनियमों द्वारा विहित रीति से और प्ररूप में रखेगा ।

(2) उपधारा (1) में यथा-वर्णित विनियमों के विरचित होने तक, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975, जो नगरपालिकाओं की बाबत वर्तमान में प्रभावी है, के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) नगर निगम निधि के लेखों की संपरीक्षा, निदेशक के नियंत्रणाधीन अलग और स्वतन्त्र संपरीक्षा अभिकरण द्वारा की जाएगी ।

(4) परीक्षण और निगम-लेखों की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए, संपरीक्षा अभिकरण निगम के सभी लेखों और सभी अभिलेखों और उनसे सम्बद्ध पत्र-व्यवहार की पहुंच रखेगा और आयुक्त संपरीक्षा अभिकरण को तुरन्त किसी रसीद या व्यय जिन्हें यह मंगवाए, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देगा ।

243. भवन बनाना.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो भवन बनाने का आशय रखता है, आयुक्त को ऐसे आशय की लिखित सूचना देते हुए ऐसे प्ररूप में और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, आयुक्त की मंजूरी के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा जो इस प्रयोजन के लिए निगम में रजिस्ट्रीकृत होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए पद अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर से स्नातक (सिविल) इंजीनियर अभिप्रेत है ।

251. भवन या संकर्म के पूरा करने की अवधि.—आयुक्त, किसी भवन के बनाए जाने या किसी संकर्म के निष्पादित किए जाने के समय, भवन या संकर्म के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसी कोई युक्तियुक्त अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसा भवन या संकर्म पूरा किया जाता है और यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा भवन या संकर्म पूरा नहीं किया है तो तत्पश्चात् वह इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से अभिप्राप्त नई मंजूरी के बिना चालू नहीं रखा जाएगा और वह तब जब कि आयुक्त उसके लिए किए गए आवेदन पर उस अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा नहीं दे देता ।

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 2007**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 46.
3. Amendment of section 84.
4. Amendment of section 161.
5. Amendment of section 243.
6. Deletion of section 251.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2007

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2007. Short title.

2. In the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), in section 46, for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 46.

“(3) There shall be a Legal Advisor-cum-Law Officer to aid and advice the Corporation in all legal matters, to be appointed by the Corporation on such terms and conditions as may be prescribed.”.

3. In section 84 of the principal Act, in sub-section(1), the existing clause (c), shall be deleted. Amendment of section 84.

4. In section 161 of the principal Act, in sub-section (3), the sign and words, “,under the control of the Director” shall be deleted. Amendment of section 161.

5. In section 243 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:— Amendment of section 243.

“Provided that every such plan and specifications shall be duly signed by a qualified Structural Engineer or Architect or Planner or Junior Engineer or Draughtsman registered with the Corporation, on payment of such fee as may be fixed by the Corporation, from time to time.”.

Deletion of
section 251.

6. Section 251 of the principal Act, shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a provision under sub-section (3) of section 46 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, to appoint Legal Advisor-cum-Prosecutor, on deputation basis to aid and advice the Corporation in all legal matters. Since a post of Law Officer has been created in the Corporation, therefore, it has been decided to substitute the words and signs "Legal Advisor-cum-Prosecutor" with the words and signs "Legal Advisor-cum-Law Officer" by substituting sub-section (3) of section 46 of the Act *ibid*.

At present, two percent surcharge on the transfer of immovable properties situated within the limits of the municipal area in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 as in force for the time being in the State of Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the municipal area, is being collected by the Corporation under section 84. A Scheme namely, 'Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)' has been launched for the development of Shimla Town for which financial aid is being provided by the Government of India subject to certain reforms. One of the reforms is to rationalize the stamp duty to bring down not more than 5%. The State Government has signed a MOA with the Government of India in this regard. The Revenue Department has already brought down the stamp duty from 8% to 5%. But due to collection of 2% surcharge by the Corporation, the percentage of stamp duty increases to 7% which is against the committed reforms under JNNURM. Therefore, it has been decided to discontinue the charging of 2% surcharge by way of deleting clause (c) of sub-section (1) of section 84 of the Act *ibid*. Further, the accounts of the Municipal Corporation Funds are audited by a separate and independent audit agency under the control of the Director, Urban Development, Himachal Pradesh as per existing provisions of section 161 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994. The Ministry of Finance, Government of India, have issued guidelines to make provision for ensuring autonomy of audit agency by allowing alternative agencies which are not controlled by the State Government. Therefore, section 161 of the Act *ibid* is required to be amended suitably. Further the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, authorises only qualified Structural Engineers to sign building plans and specifications in the Corporation area. The Architects, registered under the provisions of the Architect Act, 1972, have filed a Writ Petition challenging the above provisions with the prayer that Architects should also be allowed to sign plans in the Corporation area. The Hon'ble High Court vide its order dated 13.01.2006 has directed to permit such architects to sign such plans and specifications under the said Act. Therefore, it has been decided to make necessary provisions in the Act *ibid*.

Further, under section 251 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Commissioner while sanctioning erection of a building, has power to specify a reasonable period for completion of the erection of building from the commencement of such work. If the building or work is not completed within the period so specified, it shall not be continued thereafter without fresh sanction obtained for extension of period. This provision has been considered to be against the interest of general public. Because cost of construction always goes far beyond the estimated cost and as such generally, people with limited financial capacity can not complete the building within specified period. Therefore, it has been decided to delete section 251 of the Act *ibid*. This has necessitated amendments in Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

Shimla-171002.

Dated_____, 2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) BILL, 2007**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994(Act No. 12 of 1994).

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-in-Charge.

J. N. BAROWALIA,
Pr. Secretary (Law).

Shimla:

The_____2007.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH
MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1994 (ACT NO. 12 OF 1994) LIKELY TO
BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL**

Sections :

46. *Appointment of Joint/Assistant Commissioner and certain other officers.*—(1) The State Government may, if in its opinion it is expedient to do so in the public interest, appoint a persons or person to be called Joint/Assistant Commissioner to assist the Commissioner appointed under section 45 for the efficient performance of the functions of the Corporation and they shall be governed by such conditions of service as may be fixed by the State Government from time to time.

(2) Subject to the approval of the Corporation and rules made in this behalf the Joint/Assistant Commissioner appointed under sub-section (1) shall be subordinate to the Commissioner and shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred and imposed upon the Commissioner.

(3) There shall be a Legal Advisor-cum-Prosecutor to aid and advice the Corporation in all legal matters, to be appointed by the Corporation, by deputation, on such terms and conditions as may be prescribed.

84. *Taxes etc. to be imposed by Corporation under this Act and arrangement of certain taxes collected by Government .*—(1) The Corporation shall, for the purposes of this Act, levy the following taxes:—

- | | | | |
|------------|--|-----|-----|
| (a) to (b) | XXX | XXX | XXX |
| (c) | <p>a duty on the transfer of immovable properties situated within the limits of the municipal area in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, as in force for the time being in the State of Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the municipal area at such rate, as the State Government may, by notification, direct, which shall not be less than one percentum and more than two percentum calculated on the amount of consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument. The said duty shall be collected by the Registrar or Sub-Registrar in the shape of non-judicial stamp paper at the time of registration of the document and intimation thereof shall be sent to the Corporation immediately. The amount of the duty so collected shall be paid to the Corporation.</p> | | |

(2) Subject to the prior approval of the Government, the Corporation may for the purposes of this Act, in addition to the taxes specified in sub-section(1) levy,—

(a) to (g) XXX XXX XXX XXX XXX :

Provided that no tax shall be imposed under this sub-section unless an opportunity has been given in the prescribed manner to the residents of the municipal area to file objections and objections if any, thus received have been considered.

(3) The taxes as specified in sub-section(1) and sub-section(2) shall be levied at such rates as may, from time to time, be specified by the Government by notification shall be assessed and collected in accordance with the provisions of this Act, and the bye-laws made there under.

(4) The Government may, by special or general order, direct the Corporation to impose any tax falling under sub-section(1) or sub-section(2) not already imposed, within such period as may be specified and the Corporation shall thereupon act accordingly.

(5) If the Corporation fails to carry out any order passed under sub-section (4), the Government may by a suitable order notified in the Official Gazette impose the tax and the order so passed shall operate as if the tax had been duly imposed by the Corporation under sub-section(1) or sub-section(2), as the case may be.

161. Maintenance of accounts.— (1) There shall be kept in such manner and in such form as may be prescribed by regulations accounts of receipts and expenditure of the Corporation.

(2) Till regulations as mentioned in sub-section(1) are framed, the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Account Code, 1975, presently in force in respect of the municipalities shall be applicable.

(3) The accounts of the Municipal Corporation Fund shall be audited by a separate and independent audit agency, under the control of the Director.

(4) For the purposes of examination and audit of the Corporation accounts, the audit agency shall have access to all the Corporation Accounts and to all records and correspondence relating thereto and the Commissioner shall forthwith furnish to the audit agency any explanation concerning any receipts or expenditure which they may call for.

243. *Erection of building.*—(1) Every person who intends to erect a building shall apply for sanction by giving notice in writing of his intention to the Commission in such form and containing such information as may be prescribed by bye-laws made in this behalf.

(2) Every such notice shall be accompanied by such documents and plans alongwith specification as may be prescribed:

Provided that every such plan and specifications shall be duly signed by a qualified structural engineer who shall be registered with the municipality for the purpose.

Explanation.—For the purposes of this sub-section the expression “a qualified structural engineer” means a graduate (civil) engineer.

251. *Period for completion of building or work.*—The Commissioner when sanctioning the erection of a building or execution of a work, shall specify a reasonable period after the commencement of the building or work within which the building or work is to be completed and if the building or work is not completed within the period so specified it shall not be continued thereafter without fresh sanction obtained in the manner hereinbefore provided, unless the Commissioner on application made, therefor, has allowed an extension of that period.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007/16 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

vf/kl ipuk

f'keyk&2] 28 vxLr] 2007

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्न-बिल, 1-40/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 28-8-2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(जे० आर० गाज़टा),

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 65 का संशोधन।
4. धारा 203 का संशोधन।
5. धारा 210 का संशोधन।
6. धारा 255 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का
और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा
द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका संक्षिप्त नाम।
(संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

1994 का 13

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (जिसे इसमें धारा 3 का
इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की विद्यमान संशोधन।
उपधारा (1) के खण्ड (ii) में शब्द "बीस"के स्थान पर "दस" शब्द रखा
जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 65 के विद्यमान खण्ड (ख) का धारा 65 का
लोप किया जाएगा। संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) के खण्ड धारा 203
(ख) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— का
संशोधन।

“परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश नगरपालिका के साथ
रजिस्ट्रीकृत अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर या वास्तुविद् या
योजनाकार या कनिष्ठ अभियन्ता या ड्राफ्ट्समैन द्वारा, ऐसी फीस
के संदाय पर जो नगरपालिका द्वारा नियत की जाए, सम्यक् रूप
से हस्ताक्षरित किया जाएगा।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 210 की विद्यमान उपधारा (3) का धारा 210
लोप किया जाएगा। का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (1) में, “निदेशक धारा 255
के नियन्त्रणाधीन” शब्दों का लोप किया जाएगा। का
संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर पंचायतों को नगरपालिका परिषद् के रूप में स्तरोन्नत करने हेतु कतिपय प्रस्तावों पर इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में यथा उपबंधित बीस लाख रुपए की वार्षिक आय के मापदण्ड को पूर्ण नहीं कर पाए, यद्यपि वे पांच हजार की जनसंख्या मापदण्ड को पूर्ण करते हैं। अतः वार्षिक राजस्व उत्पादन के मापदण्ड को बीस लाख रुपए से घटाकर दस लाख रुपए करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में, नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति पर कब्जे के साथ विक्रय, दान और बंधक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश राज्य में तत्समय यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, नगरपालिका क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्ति के अंतरण पर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 65 के खण्ड (ख) के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा दो प्रतिशत अधिभार संगृहीत किया जा रहा है। शिमला शहर के विकास के लिए जवारलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0) के नाम से एक स्कीम प्रारम्भ की गई है, जिसके लिए कतिपय सुधारों के अधीन भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्टाम्प शुल्क को पांच प्रतिशत से अनधिक करके तर्कसंगत बनाना इन सुधारों में से एक है। राजस्व विभाग ने पहले ही स्टाम्प शुल्क को आठ प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत भारत सरकार के साथ एम0 ओ0 ए0 हस्ताक्षरित किया है। किन्तु निगम द्वारा दो प्रतिशत अधिभार के संग्रहण से स्टाम्प शुल्क की प्रतिशतता सात प्रतिशत तक बढ़ जाती है जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अधीन प्रतिबद्ध सुधारों के विरुद्ध है। अतः वर्तमान में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन संगृहीत किए जा रहे दो प्रतिशत अधिभार को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 203 के अधीन नगरपालिका क्षेत्र में भवन रेखांक (प्लान) को हस्ताक्षरित करने के लिए केवल स्नातक (सिविल) अभियन्ता को ही प्राधिकृत किया गया है। वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् ने, पूर्वोक्त अधिनियम के उपरोक्त उपबन्धों को इस अनुरोध के साथ चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की है कि वास्तुविद् को भी नगरपालिका क्षेत्र में रेखांकों (प्लानज) को हस्ताक्षरित करने की अनुमति दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने 13-1-2006 के अपने आदेश द्वारा ऐसे वास्तुविद् को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन रेखांक (प्लान) को हस्ताक्षर करने हेतु अनुज्ञात करने का निदेश दिया है। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 203 में तदनुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 210 के अधीन, नगरपालिका को, भवन निर्माण की मंजूरी देते समय ऐसे संकर्म (निर्माण) के प्रारम्भ होने से भवन के निर्माण के पूर्ण होने तक के लिए युक्तियुक्त अवधि

विनिर्दिष्ट करने की शक्ति है। यदि ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन या संकर्म पूर्ण नहीं होता है तो इसे अवधि के विस्तारण हेतु अभिप्राप्त नई मंजूरी के बिना, उसके बाद जारी नहीं रखा जाएगा। इस उपबन्ध को जनसाधारण के हित के विरुद्ध माना गया है, क्योंकि सन्निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) की लागत सदैव ही प्राक्कलित लागत से कहीं अधिक हो जाती है और इस प्रकार, साधारणतया सीमित वित्तीय क्षमता वाले लोग विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अतः इस शर्त का लोप करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नगरपालिका निधि की लेखों की लेखा परीक्षा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के नियन्त्रणाधीन एक पृथक और स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा की जाती है। भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय ने ऐसे विकल्पी अभिकरणों, जो राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं हैं, को अनुज्ञात कर संपरीक्षा अभिकरण की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसलिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 255 का भी तदनुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख: 2007

वित्तीय ज्ञापन

— शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

— शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख : 2007

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) के उपबन्धों के उद्घरण ।

धाराएं :

3. नगरपालिकाओं का वर्गीकरण.— (1) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार नीचे यथा विनिर्दिष्ट तीन वर्गों की नगरपालिकाएं गठित की जाएंगी,—

- (i) दो हजार से अधिक जनसंख्या वाले संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए जिसका स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व पांच लाख रुपए से अधिक है, “नगर पंचायत” ;
- (ii) पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाले छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए जिसका स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व बीस लाख रुपए से अधिक है, “नगरपालिका परिषद” ; और
- (iii) पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए जिसका स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त वार्षिक राजस्व दो करोड़ रुपए से अधिक है, और जिसे हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है, “नगर निगम”:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई नगरपालिका, ऐसे नगरीय क्षेत्रों अथवा उसके भाग में गठित नहीं की जा सकती, जिसे राज्य सरकार, क्षेत्र के आकार तथा उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा उपबन्धित की जा रही तथा उपबन्धित की जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं तथा ऐसे अन्य कारणों, जिन्हें वह ठीक समझे, को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगर के रूप में विनिर्दिष्ट करें:

परन्तु यह और कि कोई सेना छावनी या सेना छावनी का कोई भाग, किसी नगरपालिका का कोई भाग नहीं बनेगा।

स्पष्टीकरण :— इस उप-धारा में, किसी “संक्रमणकालीन क्षेत्र”, “किसी छोटे नगरीय क्षेत्र” या “किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र” से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार, क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषि इतर कार्य-कलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी ही अन्य बातों को जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार, धारा 4 में अधिकथित विधि के संप्रेक्षण के बाद, इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में, अधिसूचना द्वारा नगरपालिकाओं का गठन करेगी और उस वर्ग को विनिर्दिष्ट करेगी जिससे नगरपालिका सम्बन्धित होगी :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, विद्यमान नगरपालिकाएं तथा इस अधिनियम की अनुसूची में नगर पंचायत के रूप में अथवा नगर परिषद् के रूप में सूचीबद्ध हैं, इस धारा के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार इस रूप में गठित की गई और अधिसूचित की गई समझी जाएंगी:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अपने ऐसे करने के आशय का तीस दिन से अन्यान्य का युक्तियुक्त सुनवाई का नोटिस देने के बाद अधिसूचना द्वारा अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और किसी नगर पंचायत को नगर परिषद् के रूप में या किसी नगर परिषद् को किसी नगर पंचायत के रूप में घोषित कर सकेगी।

65. कर, जो नगरपालिका अधिरोपित करेगी.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उपबन्धों के अधधीन, प्रत्येक नगरपालिका निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगी, अर्थात् :—

- (क) निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम साढ़े सात प्रतिशत तथा अधिक से अधिक साढ़े बारह प्रतिशत कोई ऐसा कर, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे;
- (ख) यदि सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकृत की गई हो तो हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण पर विक्रय, दान और नगरपालिका क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति का कब्जा सहित बंधक लिखत पर अधिरोपित शुल्क पर, यथास्थिति, प्रतिफल की राशि, सम्पत्ति के मूल्य या लिखत में यथा उपवर्णित बंधक द्वारा प्रतिभूत राशि के दो प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जो सरकार द्वारा नियत की जाए, अधिभार के रूप में शुल्क ;

उक्त शुल्क दस्तावेज के पंजीकरण के समय न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसकी सूचना नगरपालिका को तुरन्त भेज दी जाएगी। इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि सम्बद्ध नगरपालिका को संदत्त कर दी जाएगी।

203. स्वीकृति के बिना निर्माण का प्रतिषेध.— (1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की स्वीकृति के बिना किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण, अथवा परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण का आरम्भ, नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी निर्माण का परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण करना चाहता है, नगरपालिका को ऐसे आशय का लिखित नोटिस देगा ।

(3) नगरपालिका उप-विधियों द्वारा—

(क) ऐसी रीति विहित करेगी, जिसमें किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करने के आशय का नोटिस नगरपालिका को दिया जाएगा ;

(ख) अपेक्षा करेगी कि ऐसे प्रत्येक नोटिस के साथ उस भूमि का, जिस पर ऐसे निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण किया जाना आशयित है, स्थल रेखांक और ऐसे स्वरूप के निर्माण का रेखांक और विनिर्देश तथा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी उप-विधि द्वारा अपेक्षा की जाए :

परन्तु ऐसा प्रत्येक रेखांक और विनिर्देश अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगा जो इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका में रजिस्ट्रीकृत होगा ।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद “अर्हता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियर” से स्नातक (सिविल) इंजीनियर अभिप्रेत है ।

(ग) जहां निर्माण की कारखाने के रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना प्रतीत होती है वहां, उसके सम्बन्ध में पर्याप्त आवास सुविधा की व्यवस्था की अपेक्षा करेगी :

परन्तु राज्य सरकार स्वयं अथवा किसी नगरपालिका के अभ्यावेदन पर, उप-विधियों में इस प्रकार परिवर्तन अथवा उपान्तर कर सकती है, जिससे उप-विधियां किसी नगरपालिका की विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त हो सके ।

(4) जहां इस धारा के अधीन उप-विधियां बनाई गई हैं, वहां उप-धारा (2) के अधीन कोई भी नोटिस तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा, जब तक, ऐसी उप-विधियों द्वारा अपेक्षित सूचना, यदि कोई हो, नगरपालिका को समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत नहीं कर दी गई है ।

210. पूर्णता प्रमाण-पत्र और स्वीकृति का व्यपगत होना.— (1) प्रत्येक व्यक्ति भवन के पूर्णता या भागतः निर्माण की पूर्णता के पश्चात् एक मास के भीतर कार्यपालक अधिकारी को इस निमित्त बनाई उप-विधियों द्वारा विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र के साथ ऐसी पूर्णता या पूर्णता के भाग के बारे में लिखित नोटिस द्वारा सूचना प्रदत्त करेगा या भेजेगा या प्रदत्त करवाएगा या भिजवाएगा और ऐसे भवन या उसके किसी भाग के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं कार्य-पालक अधिकारी को उपलब्ध करवाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उप-विधियों के अनुसार इस निमित्त कार्यपालक अधिकारी द्वारा जब तक अनुज्ञा प्रदान नहीं कर दी जाती तब तक कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन का अधिभोग नहीं करेगा या अधिभोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा अथवा किसी ऐसे संकर्म से प्रभावित किसी भवन या उसके भाग का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु यदि कार्यपालक अधिकारी, ऐसे पूरा होने की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से अपने इन्कार करने की संसूचना देने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है ।

(3) किसी निर्माण के परिनिर्माण या पुनःपरिनिर्माण के लिए प्रत्येक स्वीकृति जो, नगरपालिका द्वारा दी जाएगी या दी गई समझी जाएगी, ऐसी स्वीकृति की तारीख से केवल दो वर्ष या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी, यथास्थिति, नगरपालिका या कार्यपालक अधिकारी या सचिव ने धारा 203 के अधीन स्वीकृति संसूचित करते समय अनुज्ञात की हो । यदि निर्माण का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण एक वर्ष के भीतर करते समय अनुज्ञात की हो । यदि निर्माण का परिनिर्माण एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ और तीन वर्ष अथवा ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जैसी, नगरपालिका द्वारा अनुज्ञात की गई हो, पूरा न किया जाए, तो स्वीकृति समाप्त समझी जाएगी, किन्तु ऐसी समाप्ति इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन नई स्वीकृति के लिए किसी पश्चात्वर्ती आवेदन को वर्जित नहीं करेगी ।

255. लेखों की लेखा-परीक्षा.— (1) नगरपालिका-निधि के लेखों की लेखा परीक्षा-निदेशक के नियन्त्रणाधीन एक पृथक और स्वतन्त्र लेखा-परीक्षा अभिकरण द्वारा की जाएगी और लेखा-परीक्षा अभिकरण की लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए नगरपालिका के सभी लेखाओं और अन्य अभिलेखों तक पहुंच होगी ।

(2) लेखा-परीक्षा अभिकरण, लेखा परीक्षा की समाप्ति के एक मास के भीतर लेखा-परीक्षा टिप्पण की एक प्रति नगरपालिका को अग्रेषित करेगा और नगरपालिका उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति पर यथाशक्यशीघ्र त्रुटियों या अनियमितताओं का, यदि कोई रिपोर्ट में बताई गई हों, उपचार करेगी और वह की गई या की जाने को प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कथन सहित कथित रिपोर्ट की उतनी प्रतियां जितनी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हों अविलम्ब उपायुक्त और निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी ।

(3) राज्य सरकार, नगरपालिका की संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उन्हें राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी ।

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2007

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 65.
4. Amendment of section 203.
5. Amendment of section 210.
6. Amendment of section 255.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT)
BILL, 2007**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) .

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

- | | | |
|---------------------------|--|------------|
| Shot title. | 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2007. | |
| Amendment of section 3. | 2. In the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in section 3, in sub-section (1), in clause (ii), for the word “twenty”, the word “ten” shall be substituted. | 13 of 1994 |
| Amendment of section 65. | 3. In section 65 of the principal Act, the existing clause (b) shall be deleted. | |
| Amendment of section 203. | 4. In section 203 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (b), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that every such plan and specification shall be duly signed by a qualified Structural Engineer or Architect or Planner or Junior Engineer or Draughtsman who is registered with the municipality, on payment of such fee as may be fixed by the municipality.” . | |
| Amendment of section 210. | 5. In section 210 of the principal Act, the existing sub-section (3) shall be deleted. | |
| Amendment of section 255. | 6. In section 255 of the principal Act, in sub-section(1), the words “under the control of the Director” shall be deleted. | |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Certain proposals for upgradation of Nagar Panchayats as Municipal Council could not be processed due to the fact that they do not fulfil annual income criteria of rupees twenty lakh as provided in clause (ii) of sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, though they fulfil population criteria of five thousand. Thus, it has been decided to reduce criteria of annual revenue generation from rupees twenty lakh to ten lakh. Further, at present, 2% surcharge on the transfer of immovable properties situated within the limits of the municipal area in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 as in force for the time being in the State of Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the municipal area is being collected by the municipalities under clause(b) of sub-section 65 of the Act *ibid*. A scheme namely, 'Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)' has been launched for the development of Shimla Town for which financial aid is being provided by the Government of India subject to certain reforms. One of the reforms is to rationalize the stamp duty to bring down not more than 5%. The Revenue Department has already brought down the stamp duty from 8% to 5%. The State Government has signed a MOA with Government of India in this regard. But due to collection of 2% surcharge by the municipalities, the percentage of stamp duty goes upto 7% which is against the committed reforms under JNNURM, therefore, it has been decided to abolish 2% surcharge which is being presently collected under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994. Further, under section 203 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, only graduate (Civil) Engineer have been authorized to sign building plan in the municipal area. The Architects, registered under the provisions of the Architect, Act, 1972, have filed a Writ Petition challenging the above provision of the Act *ibid* with the prayer that Architects should also be allowed to sign plans in the municipal area. The Hon'ble High Court vide its order dated 13.01.2006 has directed to permit such Architects to sign plan under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, therefore, section 203 of the Act *ibid* is required to be amended accordingly. Further, under section 210 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the municipality while sanctioning erection of a building, has power to specify a reasonable period for completion of the erection of building from the commencement of such work. If the building or work is not completed within the period so specified, it shall not be continued thereafter without fresh sanction obtained for extension of period. This provision has been considered to be against the interest of general public. Because cost of construction always goes far beyond the estimated

cost and as such, generally, people with limited financial capacity can not complete the building within specified period, therefore, it has been decided to delete this condition.

Further, at present the accounts of the Municipal Fund are audited by a separate and independent audit agency under the control of the Director, Urban Development, Himachal Pradesh. The Ministry of Finance, Government of India, have issued guidelines to make provision for ensuring autonomy of audit agency by allowing alternative agencies which are not controlled by the State Government. Thus, it has also been decided to amend section 255 of the Act *ibid* accordingly. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)

Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Dated _____, 2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2007

A

BILL

Further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(13 of 1994).

(KAUL SINGH THAKUR),
Minister-in-Charge.

(J. N. BAROWALIA),
Pr. Secretary(Law).

SHIMLA :

The....., 2007.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH
MUNICIPAL ACT, 1994 (ACT NO.13 OF 1994) LIKELY TO BE
AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL**

Sections:

3. Classification of municipalities.— (1) There shall be constituted three classes of municipalities in accordance with the provisions of this section as specified below :—

- (i) “Nagar Panchayat” for a transitional area with population exceeding two thousand and generating annual revenue exceeding rupees five lakhs for the local administration;
- (ii) “Municipal Council” for a smaller urban area with population exceeding five thousand and generating the annual revenue exceeding rupees twenty lakhs for the local administration;
- (iii) “Municipal Corporation” for a larger urban area with population exceeding fifty thousand and generating the annual revenue exceeding rupees two crores for the local administration and which has been declared to be a municipal area under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994:

Provided that a municipality under this section may not be constituted in such urban areas or part thereof as the State Government may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as it may deem fit, by notification, specify to be an industrial township:

Provided further that no cantonment or part of a cantonment shall form part of a municipality.

Explanation.— In this sub-section, “a transitional area”, “a smaller urban area” or “a larger urban area” means such area as the State Government may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as the State Government may deem fit, specify by notification for the purpose of this section.

(2) The State Government shall, by notification, constitute the municipalities and specify the class to which a municipality shall belong in accordance with the provisions of this section after observing the procedure as laid down in section 4:

Provided that the municipalities existing at the commencement of this Act and listed as Nagar Panchayat or as Municipal Council in the Schedule to this Act, would be deemed to have been constituted and notified as such, under and in accordance with the provisions of this section:

Provided further that the State Government may, after giving a reasonable notice of not less than thirty days of its intention to do so, amend the schedule, by notification and declare any Nagar Panchayat as a Municipal Council or any Municipal Council as a Nagar Panchayat.

65. Taxes which municipality shall impose.— For the purpose of this Act and subject to the provisions thereof every municipality shall impose the following taxes, namely:—

- (a) a tax payable by the owner on buildings and lands which shall not be less than seven and half percentum and more than twelve and a half percentum, as the State Government may, by notification, direct, of the annual value of such buildings and lands;
- (b) if so authorized by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899(2 of 1899) in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in municipal area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two percent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument;

the said duty shall be collected by the Registrar or Sub-Registrar in the shape of non-judicial stamp paper at the time of registration of the document and intimation thereof shall be sent to the municipality concerned.

203. Prohibition to erect buildings without sanction.— (1) No person shall erect or re-erect or commence to erect or re-erect any building without the sanction of the municipality.

(2) Every person who intends to erect or re-erect any building shall give notice in writing to the municipality of such intention.

- (3) The municipality shall by bye-law—
 - (a) prescribe the manner in which notice of the intention to erect or re-erect a building shall be given to the municipality;
 - (b) require that with every such notice shall be furnished a site plan of the land on which it is intended to erect or re-erect such building and a plan and specification

of the building, of such character and with such details as the bye-law may require:

Provided that every such plan and specifications shall be duly signed by a qualified structural engineer who shall be registered with the municipality for the purpose;

Explanation.— For the purposes of this clause the expression “ a qualified Structural Engineer” means a graduate(civil) engineer; and

- (c) where the building appears likely to be use as a factory, require the provision of adequate housing accommodation in connection therewith:

Provided that the State Government may of its own or on a representation from any municipality alter, vary or modify the bye-laws so as to suit the particular needs of the municipality.

- (4) Where bye-laws have been framed under this section , no notice under sub-section(2) shall be considered to be valid until the information, if any, required by such bye-laws has been furnished to the satisfaction of the municipality.

210.Completion certificate and lapse of sanction.— (1) Every person shall, within one month after the completion of the erection of the whole or part of the building, deliver or sent or cause to be delivered or sent to the Executive Officer a notice in writing of such completion or part of completion accompanied by a certificate in the Form prescribed by bye-laws made in this behalf and shall give to the Executive Officer all necessary facilities for the inspection of such building or part of the building.

- (2) No person shall occupy or permit to be occupied any such building or use or permit to be used any building or part thereof until permission has been granted by the Executive Officer in this behalf in accordance with the bye-laws made under this Act:

Provided that if the Executive Officer fails within a period of thirty days after the receipt of the notice of completion to communicate his refusal to grant such permission such permission shall be deemed to have been granted.

- (3) Every sanction for the erection or re-erection of any building which shall be given or be deemed to have been given by a municipality shall remain in force for two years only from the date of such sanction or for such longer period as the municipality or the Executive Officer or Secretary, as the case may be, may have allowed when conveying sanction under section 203. Should the erection or re-erection of the building not have been commenced within one year and completed within three years or such longer period as may have been

allowed by the municipality the sanction shall be deemed to have lapsed but such lapse shall not bar any subsequent application for fresh sanction under the foregoing provisions of the Act.

255. Audit of accounts.— (1) The accounts of the municipality fund shall be audited by a separate and independent audit agency under the control of the Director and the audit agency shall, for the purpose of audit have access to all the accounts and other records of the municipality.

(2) The audit agency shall within one month of the completion of the audit forward the copy of the audit note to the municipality and on receipt of the said report, the municipality shall, as soon as may be, remedy defects or irregularities if any pointed out in the report and shall forward without delay to the State Government through the Deputy Commissioner and the Director, so many copies of the said report as may be required by the State Government with a brief statement of the action, if any, taken or proposed to be taken thereon.

(3) The State Government shall on receipt of the audit report of the municipalities, lay them before the State Legislature.

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2007.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (साधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2006/16 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 28 अगस्त, 2007

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्न.-बिल०, 1-41/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 12) जो आज

2037-राजपत्र/2007-7-9-2007

(5025)

दिनांक 28 अगस्त, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश माता—पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन)
विधेयक, 2007

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन ।

**हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन)
विधेयक, 2007**

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001
(2001 का 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन) अधिनियम, 2007 है ।

धारा 3 का
संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 की धारा 3 की उपधारा (1) में, “,जिसकी आय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए अधिकथित स्तर से नीचे है तथा” चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा। 2001 का 19

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सरकार माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 के साथ पठित अनुच्छेद 41 में अधिकथित सिद्धान्तों की प्राप्ति के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि माता-पिता और आश्रितों, जो विशेषता वृद्ध हैं तथा जिन्हें अपने नजदीकी सम्बन्धियों द्वारा वस्तुतः देखभाल की आवश्यकता है, की देखभाल तथा भरण-पोषण सुनिश्चित किया जा सके। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार केवल गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति ही भरणपोषण आदेश हेतु आवेदन करने के पात्र हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के अधिकांश व्यक्ति भी निराश्रित हैं क्योंकि उनकी देखभाल उनके नजदीकी सम्बन्धियों द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है और उनमें से कुछ तो वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, करुणामय तथा दयनीय जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार की राहत के हकदार नहीं हैं। इसलिए उन व्यक्तियों, जो गरीबी रेखा से ऊपर के हैं तथा अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, को भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के लाभ प्रदान करने के लिए उपरोक्त अधिनियम का उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख : 2007.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण (संशोधन)
विधेयक, 2007

हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (2001 का 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री।

जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख: 2007

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश माता-पिता और आश्रित भरणपोषण अधिनियम, 2001 (2001 का 19) के उपबन्धों के उद्घरण।

धारा :

3. भरणपोषण आदेश के लिए आवेदन.—(1) कोई व्यक्ति, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, “जिसकी आय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए अधिकथित स्तर से नीचे है” तथा और हिमाचल प्रदेश राज्य का निवासी है—

- (i) माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में, उसके एक या अधिक सन्तान या पौत्र-पौत्री;
- (ii) पत्नी की दशा में—उसका पति;
- (iii) अप्राप्तवय पुत्र या अविवाहित पुत्री की दशा में, उसका पिता और जहां पिता की मृत्यु हो चुकी है उसकी माता; और
- (iv) माता-पिता, पितामह-पितामही, पत्नी, अप्राप्तवय पुत्र या अविवाहित पुत्री से भिन्न आश्रित की दशा में यदि ऐसे आश्रित ने अपने पूर्वज की सम्पदा में कोई भाग वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया है — वह व्यक्ति जो भाग लेता है ;
से अपने भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता प्रतिमास पांच हजार रुपये से अधिक या कोई अन्य कालिक संदाय या एकमुश्त उसे सदत्त करने के आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(2) अनुमोदित व्यक्ति या संगठन जिसकी देख-रेख में माता-पिता, सन्तान या आश्रित रहता है, आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा कि, यथास्थिति, माता-पिता, पत्नी, सन्तान या आश्रित के भरण पोषण के खर्च और व्यय चुकाने के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी, अनुमोदित व्यक्ति या संगठन को प्रतिमास पांच हजार रुपए से अधिक मासिक भत्ता या कोई कालिक या एकमुश्त संदाय संदत्त करेगा ।

(3) जहां माता-पिता, पत्नी, सन्तान या आश्रित अनुमोदित व्यक्ति या संगठन की देख-रेख में नहीं रहता है, वहां, उक्त माता-पिता, पत्नी, संतान और आश्रित के भरण-पोषण के युक्तियुक्त खर्च और व्यय काटने के पश्चात्, मासिक भत्ता अन्य कालिक या एकमुश्त संदाय के शेष का कोई भाग, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता, पत्नी, संतान और आश्रित के लिए न्यास के रूप में रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए, माता-पिता अपना भरणपोषण करने में असमर्थ समझे जाएंगे यदि उनकी कुल या प्रत्याशित आय और अन्य वित्तीय स्रोत उन्हें रोटी, कपडा और मकान सहित (किन्तु वहां तक सीमित न रह कर) बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए अपर्याप्त है ।

**THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND
DEPENDANTS (AMENDMENT) BILL, 2007****ARRANGEMENT OF CLAUSES*****Clauses:***

1. Short title.
2. Amendment of section 3.

THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND DEPENDANTS (AMENDMENT) BILL, 2007

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and
Dependants Act, 2001 (Act No. 19 of 2001).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants (Amendment) Act, 2007. Short title.

19 of 2001 2. In the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001, in section 3, in sub-section (1), the words "having income below the level laid down for persons living below the poverty line and" shall be deleted. Amendment of section 3.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependents Act, 2001 was enacted with the objective of securing the principles laid down in article 41 read with article 38 of the Constitution of India and to ensure the care and maintenance of parents and dependents particularly who are in old age and really need care from their kith & kins. As per provisions of section 3 of the Act *ibid*, only the persons who are living below the poverty line are eligible to apply for the maintenance order, whereas large number of persons belonging to above poverty line are also destitute as their kith and kins are not looking after them. Such persons have been forced to leave their homes and some of them are residing in old age homes. Such persons are not entitled for any relief under the Act despite of the fact that they are leading compassionate and miserable life. Thus, in order to extend the benefits of the provisions of the said Act also to the persons living above the poverty line and are unable to maintain themselves, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

Shimla :

Dated: 2007.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—

**THE HIMACHAL PRADESH MAINTENANCE OF PARENTS AND
DEPENDANTS (AMENDMENT) BILL, 2007**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Maintenance of Parents and Dependants Act, 2001
(Act No.19 of 2001).*

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

J. N. BAROWALIA,
Pr. Secretary (Law).

Shimla:
The....., 2007.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH
MAINTENANCE OF PARENTS AND DEPENDANTS ACT, 2001 (ACT
No. 19 OF 2001) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT
BILL****Section:**

3. Application for maintenance order.—(1) Any person who is unable to maintain himself and having income below the level laid down for persons living below the poverty line and is resident in the State of Himachal Pradesh, may apply to the Tribunal for an order—

- (i) In case of a parent or grand parent, that one or more of his children or grand children;
- (ii) In case of wife, that her husband;
- (iii) In case of minor son or unmarried daughter, that his or her father and where father is dead, his or her mother; and
- (iv) in case of dependant (other than a parent, grand parent, wife, minor son or unmarried daughter) if such dependant has not obtained, by testamentary or intestate succession, any share in an estate of his ancestor that the persons who take the share, shall pay him a monthly allowance, not exceeding five thousand rupees per mensem, or any other periodical payment or a lump-sum for his maintenance.

(2) An approved person or organization in whose care a parent, wife, child or dependant resides may apply to the Tribunal for an order that the respondent shall pay to the approved person or organization a monthly allowance not exceeding five thousand rupees per mensem or any other periodical payment or a lump-sum for the purpose of defraying the cost and expenses of maintaining that parent, wife child or a dependant, as the case may be.

(3) Where a parent, wife child or dependent ceases to be in the care of the approved person or organization, any part of the monthly allowance, other periodical payment or lump-sum remaining after deducting the reasonable cost and expenses of maintaining the parent, wife, child and the dependant shall be held in trust for such parent, wife, child and the dependant, as the case may be.

Explanation:—For the purpose of this section, a parent is unable to maintain him, if his total or expected income and other financial resources are inadequate to provide him with basic amenities and basic physical needs including (but not limited to) shelter, food and clothing.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2007 / 16 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th September, 2007

No. Home-B (B)15-10/2005-HC.—In exercise of the powers vested in him under Sub-Section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Vikas Sood, Inspector Registration-cum-Stamp Auditor (Tehsildar), H.P.Sectt., to be the Executive Magistrate with the powers of Executive Magistrate under the said code to be exercised within the local limits of Tehsil, Shimla for the purpose of attestation of affidavits/documents, with immediate effect. He shall cease to function as Executive Magistrate on his transfer from the present post/assignment.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

ELECTION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171009, the 3rd September, 2007*

No.5-21/2006-ELN.—In exercise of the powers vested under Section 32 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to identify the following posts for the purpose of three percent reservation in direct recruitment for various categories of posts in Election Department in respect of Class-III & IV posts for Disabled Persons of Himachal Pradesh:—

Sr. No.	Name of post/ Class	Sanctioned Strength	Direct recruitment.	Reservation percentage.	Backlog w.e.f. 7-2-1996 onwards.
1.	Election Kanungo, Class-III, (Non-Gazetted).	70	100%	3%	1
2.	Clerks, Class-III, (Non-Gazetted).	77	90%	3%	—
3.	Peon & Chowkidar. Class-IV, (Non-Gazetted).	86	100%	3%	—

The three percent reservation is further to be allocated among visually impaired, hearing impaired and orthopedically handicapped categories in the ratio of one percent each w.e.f. 7-2-1996 i.e. from the date of commencement of the Act *ibid*, subject to the availability of the suitable candidates, and in case no suitable person is available, the vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year; and if in the succeeding year also suitable person with disability is not available, it shall first be filled up by interchange amongst the three categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the Department shall fill up the vacancy by appointing other than a person with disability.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to declare that in case the appointing agency/authority is satisfied that the nature of vacancies is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies can be interchanged amongst the three categories with the prior approval of the competent authority.

By order,
MANISHA NANDA,
Secretary.

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, 27th August, 2007*

No. HFW-B(B)10-1/2003-loose.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following doctors shall retire from Government service on attaining the age of superannuation from the date shown against each:—

Sr. No.	Name & Designation	Date of birth	Date of retirement
1.	Dr. Kuldeep Sood, Professor & HOD, Anatomy, IGMC, Shimla	11.6.1950	30.6.2008
2.	Dr. M.L.Gupta, Asstt. Prof. Microbiology, IGMC, Shimla	30.6.1950	30.6.2008
3.	Dr. Ashok Bhardwaj, Professor & HOD, Community Medicine IGMC, Shimla.	15.7.1950	31.7.2008
4.	Dr. N.L.Sharma, Professor & HOD, Skin & VD (Dermatology) IGMC, Shimla.	1.11.1950	31.10.2008
5.	Dr. S. M.Mehta, Asstt. Prof. Orthopaedics, Dr.RPGMC Kangra at Tanda .	29.12.1950	31.12.2008

By order,
Sd/-

Principal Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2007

सं पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0-(5) 284 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मगर, तहसील सदर, जिला मण्डी मे मगर पाधरु सडक के निर्माण हेतु सडक भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा-बिस्वा
मण्डी	सदर	मगर	24	18-10-03
			किता-1	18-10-03

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2007

सं पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 285 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव वैरी दडोलां, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर में वैरी दडोलां गोविन्द सागर पर वैरी दडोलां पूल के लिए सम्पर्क सडक (वैरी दडोलां साईड) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्तियां दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा-बिस्वा
बिलासपुर	झण्डूता	वैरी दडोलां	79	3-14
			81	0-5
			82	0-15
			390 / 86	0-5
			156	5-19
			157	0-18
			158	1-17
			183	0-13
			185	13-1
			190	4-13
			191	0-6
			192	0-6
			395 / 1	6-0
			410 / 396	2-0
	कुल जोड़	कित्ता	14	40-12

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3-9-2007

सं पी0बी0डब्ल्यू00(बी0)एफ(5) 279 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव करेडु एवं बढई, तहसील व, जिला शिमला में चक्कर से न्यायिक परिसर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा(हैक्टेयर में)
शिमला	शिमला	करेडू	1410 / 1	24-75
			1411 / 1	11-37
			1413	04-20
			1414	04-08
			1415	05-27
			1416	04-60
			1417	02-40
			1419	12-50
			1420	02-04
			1421	24-79
			1422 / 1	111-12
			1438 / 1	62-50
			1438 / 2	131-85
			1439	33-05
			1441 / 1	3484-99
			1446 / 1 / 1	96-12
			किता : 16	4015-63
शिमला	शिमला	बढई	1347 / 703	0-2
		कुल जोड	किता : 1	0-2

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2007

सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)ए०-(7) 1-26 / 2004.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गतेड, तहसील अर्की, जिला सोलन में नम्होल बहादुरपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग दक्षिण क्षेत्र शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(विघा विस्वा)
सोलन	अर्की	गतेड	4 / 1	1-1
			99 / 3 / 1	1-18
			97 / 1 / 1	0-16
			97 / 1 / 2	0-2
			किता-4	3-17

आदेश द्वारा,
हस्ता / -
प्रधान सचिव।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th Sept., 2007

No. PBW-A-B(1)-3/2007.— In order to strengthen Quality Management and Monitoring mechanism in H.P.PWD, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of Quality Management & Monitoring Units in H.P.PWD at North Zone, Dharamshala and Central Zone, Mandi.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to create two posts of Executive Engineer (Quality Assurance) in the pay scale of Rs. 12,000-15,500 for the above units with immediate effect in public interest with stipulation that both these posts will be on co-terminus with the World Bank project period and thereafter these posts will stand automatically abolished.

This has been issued with the prior approval of the Finance Department obtained vide their U.O.No.50466798-Fin-F/2007 dated 10.08.2007.

By order,
Sd/-
Principal Secreeta

PUBLIC WORKS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 5th September, 2007*

No.PBW-A-B(6)-7/2007-loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer/posting of Sh.Manoj Kumar, Assistant Engineer (Civil), HP, PWD Sub-Division, Nankhari to HP, PWD Sub-Division, Kalpa against vacancy with immediate effect in the public interest.

By order;

Sd/-

*Principal Secretary.***PUBLIC WORKS DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-2, the 4th August, 2007*

No.PBW-A-B(6)-28/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of the following Junior Engineers (Mech.) HP, PWD to the post of Assistant Engineer (Mech), Class-I (Gazetted) purely on adhoc basis as a stopgap arrangement in the pay scale of Rs.7880-13500 (with initial start of Rs.8000/-) with effect from taking over the charge as such in the public interest:—

1.	Name of Official	D.O.B.
1.	Sh.Bhumi Chand	4.1.54
2.	Sh.Amar Singh Dhiman	2.1.54
3.	Sh.Kartar Chand	20.11.53
4.	Sh.Man Chand	13.12.56

2. The above adhoc promotions shall not confer any right whatsoever for continuation/ seniority or regularization.

3. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of the above officers on their promotion with immediate effect in the public interest as under:-

Sl. No.	Name of Officer	From	To
1.	Sh.Bhumi Chand	On promotion	SBC, Mechanical Sub-Division HP, PWD, Dhalli against vacancy
2.	Sh. Amar Singh Dhiman	On promotion	HP, PWD, Jogindernagar Mechanical Sub-Division against vacancy
3.	Sh.Kartar Chand	On promotion	Mechanical Sub-Division HP, PWD, Kumarsain against vacancy
4.	Sh.Man Chand	On promotion	Mechanical Sub-Division HP, PWD, Karga (L&S) against vacancy

4. The promotion of above officers is conditional to their joining at their new place of posting within 7 days of the issue of this notification. Their failure to join at their new place of

posting within the stipulated period shall be treated as refusal to promotion and next in the panel will be promoted. No correspondence/representation will be entertained in this behalf.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)ए०-7(1)118/2005.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव पंच जन/398, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 20 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र(विघा विस्वा)
मण्डी	जोगिन्द्रनगर	पंचजन/398	647/1	0-14-8
			648/1	0-9-18
			649/1	0-1-9
			655/1	0-2-4
			781/656/1	0-16-19
			659/1	0-11-13
			684/1	0-4-15
			685/1	0-10-11
			686/1	0-9-4
			687/1	0-4-13
			688/1	2-14-12
			700/1	0-16-4
			699/1	0-0-4
			765/705/1/1	0-3-6
		कुल जोड	किता- 14	8-0-10

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 246 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भलेती पठियां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना- अग्धार- मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ० क्षेत्र कांगडा (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकबा (हैक्टरों में)
ऊना	बंगाणा	भलेती पठियां	60 / 1	0-00-77
			61 / 1	0-00-48
			62 / 1	0-00-13
		किता;	3	0-01-38

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ(5) 249 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सूरड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना- अग्धार- मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ० क्षेत्र कांगडा (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकबा (हैक्टरों में)
ऊना	बंगाणा	सूरड़ा किता;	$\frac{226}{1} / \frac{200}{1} / 1$	$\frac{0-00-44}{0-00-44}$

आदेश द्वारा,
हस्ता/—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ(5) 255/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वाहल, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना- अग्धार- मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ० क्षेत्र कांगडा (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	रकबा (हैक्टरो में)
ऊना	बंगाणा	वाहल	110 / 1	0-00-70
			112 / 1	0-00-49
			113 / 1	0-00-38
			116 / 1	0-00-18
			143 / 1	0-00-11
			145 / 1	0-00-12
			<hr/>	<hr/>
		किता;	6	0-01-98

आदेश द्वारा,
हस्ता / -
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू० (बी०)एफ(5) 261 / 2007.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लठियाणी तहसील बंगाणा जिला ऊना मै ऊना-अग्घार-मण्डी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ० क्षेत्र कांगडा (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (हैक्टरो में)
ऊना	बंगाणा	लठियाणी	178	0-01-29
			391 / 1	0-00-20
			392 / 1	0-00-09
			396	0-00-38
			400	0-00-46
			404 / 1	0-04-90
			414 / 1	0-00-30
			688	0-00-81
			695	0-00-22
			696	0-00-12
			777 / 1	0-00-03
			859 / 1	0-00-08
			1005	0-08-24
			1007	0-06-15
			1008	0-03-64
			1010 / 1	0-15-30
			1016 / 1	0-00-06
			1034 / 1	0-00-55
			1138 / 1	0-00-14
			1139	0-00-72
			1146	0-04-61
			1147 / 1	0-00-06
			1148 / 1	0-00-14
			1149 / 1	0-00-24
		किता;	24	0-48-73

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अगस्त, 2007

सं० पी०बी०डब्ल्यू (बी०)एफ(5) 262 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव त्यासर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना-अगधार-मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगडा (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकबा (हैक्टरो में)
ऊना	बगं णा	त्यासर	838 / 1	0-00-96
			854 / 1	0-00-34
			970 / 1	0-00-42
			887 / 1	0-00-08
			1260 / 1	0-00-77
		किता;	5	0-02-57

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 2007

संख्या: पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ (5)272/2006.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत ग्राम जमरोटी, तहसील अर्की, जिला सोलन में कुनिहार बैन्जहट्टी ब्रम्हपुखर सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा. 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. भूमि का रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षेत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला 3 में किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा-बिस्वा
सोलन	अर्की	जमरोटी	133 / 2 / 1	0-14
		कुल जोड	किता-1	0-14

आदेश द्वारा,
हस्ता/-
प्रधान सचिव।

